विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त $2\frac{1}{2}$ बटालियन उपलब्ध की गई थी। इन अतिरिक्त बटैलियनों को वापिस बुला लिया गया है और इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की चार बटैलियन राज्य सरकार के पास है।

बिहार के विकास के लिये पांचवीं योजना में नियतन

74. **श्री युवराज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार के योजनाबद्ध विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि का नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) इस राज्य की जनसंख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस राज्य को कब तक सहायता देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के लिए 24 और 25 सितम्बर, 1976 को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सभी राज्यों की योजना के आकार को अन्तिम रूप दिया गया था। पांच वर्षों की सम्पूर्ण अवधि के लिए बिहार राज्य का परिव्यय 1,296.06 करोड़ रुपये है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन सभी राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए फार्मूले के आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय न केवल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार प्रकट किए गए पिछड़ेपन का ही ध्यान रखा जाता है, बल्कि सम्बन्धित राज्यों द्वारा संसाधन जुटाने के लिए किए गये प्रयासों और उनकी विशेष समस्याओं का भी ध्यान रखा जाता है।

आपात स्थिति के दौरान मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये कार्यकर्ता

75. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25–26 जून, 1975 को आपात स्थिति लागू होने पर केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार अथवा उसके अधिकारियों को किन श्रेणियों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के आदेश भेजे गये थे; और

(ख) क्या गिरफ्तारी सम्बन्धी उक्त आदेश अथवा अन्य आदेश अभी भी उपलब्ध है ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) जून, 1975 में आपात स्थिति की उद्घोषणा के समय, गिरफ्तार किए जाने वाले सरकारी अधिकारियों की श्रेणियों का ठीक ठीक उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को कोई आदेश जारी नहीं किए गये थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Inquiry into atrocities on Political Prisoners in Jails during Emergency

76. SHRI HARIVISHNU KAMATH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to institute a public independent inquiry into the atrocities perpetrated on political prisoners in various jails during the period of Emergency, from June 26, 1975 to date; and

(b) if so, when, and its terms of reference ?